झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

सिविल समीक्षा संख्या 64/2020

1.रंजीत कुमार दुबे

2.अनिमेष कुमार मिश्रा

3.सुजीत कुमार

4.श्री कांत कुमार

5.उपेंद्र मेहता

6.सत्य नारायण पाल

7.अमृत यादव

8.धीरेंद्र पाल

9. ओम प्रकाश पांडे

10.राधा नंद भट्ट

11. रघुराज प्रसाद गुप्ता.....

याचिकाकर्ता गण

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची

3 प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू

4.उपायुक्त, पलामू..... प्रतिवादी

5.संजीव कुमार पांडे

6.धर्मेंद्र कुमार सिंह

7. सुरेंद्र सिंह

8.सुजीत कुमार

9.शशिकांत कुशवाहा

10. प्रेम प्रकाश @प्रेम प्रकाश

11 मृत्युंजय कुमार सिंह

12. अजय कुमार सिंह

13. संतोष कुमार सिंह हस्तक्षेप करने वाले/प्रतिवादी

14. सुधाकर दुबे

15. ऐनुल अंसारी

16 मनोरंजन पाठक

17. कमला प्रसाद

18. शैलेंद्र मिश्रा

19. सतीश कुमार शर्मा

20. अभय पासवान

21. उपेंद्र कुमार

22 अशोक कुमार दुबे

23 मनोज कुमार पटेल

24. फिरोज दुरईज खान

25. चंदेश्वर पासवान

26.इरफ़ान अहमद

27. प्रफुल्ल कुमार सिंह

28. राहुल कुमार दुबे

29. अजय कुमार गुप्ता

30. मनोज कुमार यादव

31. मोहम्मद इरफान

32. अनुज शर्मा

33. ओम प्रकाश मेहता

34. कार्तिक कुमार

35. ललन कुमार

36. अभिषेक चौबे.....प्रोफोर्मा उत्तरदातागण

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री राजेन्द्र कृष्ण, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः श्री श्रीनु गारापति, एससी-III

06/09.04.2021 याचिकाकर्ताओं के विद्वत वकील श्री राजेन्द्र कृष्ण और प्रतिवादियों के विद्वत वकील श्री श्रीनु गरपति को सुना।

2. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर इस नागरिक समीक्षा याचिका को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया ।किसी भी पक्ष ने ऑडियो-वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

3 याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका संख्या 1241/2020 में दिनांक 07.10.2020 को पारित आदेश की समीक्षा के लिए इस सिविल समीक्षा याचिका को दायर किया गया है।

4. याचियों के विद्वत वकील श्री राजेन्द्र कृष्ण प्रस्तुत करते हैं कि कथित आदेश दिनांक 07.10.2020 के द्वारा दो रिट याचिकाओं का निपटान किया गया था.हालांकि वर्तमान पुनर्विचार याचिका केवल उस रिट याचिका के 34 याचिकाकर्ताओं के संबंध में रिट याचिका संख्या 1241/2020 के संबंध में दायर की गई है।

5. याचियों के लिए झुके हुए वकील प्रस्तुत करते हैं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश की समीक्षा की आवश्यकता है कि कोई साक्षात्कार नहीं लिया गया था और केवल परामर्श दिया गया था और इस न्यायालय ने अन्य मामलों के साथ इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित पहले के आदेशों को दोहराया है.वह प्रस्तुत करते है कि ये याचिकाकर्ता रिट याचिका संख्या 6709/ 2017 में पार्टी-प्रतिवादी नहीं थे और उस मामले की दृष्टि से उस रिट याचिका में जारी किए गए निर्देश इन याचिकाकर्ताओं पर बाध्यकारी नहीं हैं.इन आधारों पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वत वकील प्रस्तुत करते हैं कि समीक्षा याचिका को कृपया अनुमति दी जाए.

6. श्री श्रीनु गारपति, प्रतिवादी राज्य की ओर से पेश होने वाले एससी-III ने प्रस्तुत किया है कि जिस आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई है, उसमें रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है।

वह प्रस्तुत करते है कि रिट याचिका संख्या 6709/2017 में समन्वय पीठ द्वारा पारित पहले के आदेश को केवल इस न्यायालय द्वारा दोहराया गया है.वह आगे प्रस्तुत करते है कि उक्त आदेश की माननीय खंडपीठ द्वारा पहले ही पुष्टि की जा चुकी है और इस मामले को देखते हुए समीक्षा आदेश के लिए कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है.वह आगे प्रस्तुत करता है कि संशोधन याचिका दायर

करके कुछ कारण बताओ याचिका को रिकॉर्ड पर लाया गया है और यह कारण बताओ याचिका पहले की रिट याचिका का हिस्सा नहीं था और उस मामले को देखते हुए समीक्षा याचिका की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

7. पक्षकारों के विद्वत वकील को काफी देर तक सुना।

8. दिनांक 07.10.2020 के आदेश का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि इस न्यायालय ने केवल रिट याचिका संख्या 6709/2017 में समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश को दोहराया गया है ।संक्षिप्तता के लिए, दिनांक 07.10.2020 के आदेश का अंतिम भाग नीचे उद्धृत किया गया हैः -

दिनांक 15.06.2020 के आदेश के अनुसार, यह पाया गया कि कोई भी प्रगति, रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगी।यह स्वीकार तथ्य है कि याचिकाकर्ता 14 मार्च, 2020 के आक्षेपित पत्र के संदर्भ में आगे की काउंसलिंग में उपस्थित हुए हैं।पहले की रिट याचिका में जारी किए गए निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक बार प्रतिवादियों द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के बाद, यह खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों को नहीं बदल सकता है.इस मामले के दृष्टिकोण से, रिट याचिका का निपटान विज्ञापन का सख्ती से पालन करने के लिए न्यायालय के निर्देश को दोहराते हुए किया जा रहा है.याचिकाकर्ता पहले ही नोटिस के अनुसार पेश हो चुके हैं।यह उम्मीद की जाती है कि प्रत्यर्थी प्राधिकारी विशेष रूप से पैराग्राफ 11 और 12 में रिट याचिका (एस) संख्या 6709/2017 में पारित रिट कोर्ट के निर्देश पर विचार करेगा और उसके बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

उपरोक्त अवलोकन और निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

याचियों के लिए यह खुला है कि यदि वे योग्यता सूची के अंतिम परिणाम से व्यथित हैं, तो वे कानून के अनुसार उचित कदम उठा सकते हैं.

आईए संख्या 4394/2020 और आईए संख्या 4392/2020 को कारण बताओ नोटिस के निपटारे को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।

9. दिनांक 07.10.2020 के आदेश के अंतिम भाग को ध्यान में रखते हुए, यह पता चलता है कि इस न्यायालय ने केवल रिट याचिका संख्या 6709/2017, विशेष रूप से पैरा 11 और 12 में

को-ऑर्डिनेट बेंच द्वारा पारित पहले के आदेश को दोहराया है, जिसकी पुष्टि खंडपीठ बेंच द्वारा की गई थी।

बाद का कारण-बताओ रिट याचिका का हिस्सा नहीं था।रिट याचिका का निपटान सह-समन्वय पीठ द्वारा पारित पहले के आदेश को दोहराते हुए किया गया, जिसकी खंडपीठ द्वारा पुष्टि की गई है।इस प्रकार, अभिलेख में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है।

10. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती है.तदनुसार, इस सिविल समीक्षा याचिका को खारिज किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, जे)

सत्यार्थी/-